(c) Yes, Sir.

(d) Flats are allotted from time to time depending upon availability of flats for allottment in the respective categories.

(e) and (f)D.D.A. proposes to hold the next draw for allotment of 1300 flats in M.I.G. category in March, 1992.

*70 *[Transferred to the5th March,* 1992)

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

*71. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :**
श्री सुनील बसु राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ अनिवासी उद्योगपतियों ने बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को सुचारू ढंग से चलाने के लिये सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) 'इस्को' को सुचारू रूप से चलाने के लिये कोई विस्तृत विशिष्ठ सुझाव किसी अनिवासी भारतीय उद्योगपति से प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि, सरकार को लन्दन स्थित कापरो ग्रुप लिमिटेड जिसके साथ कि अनिवासी भारतीय, श्री स्वराज पाल बद्ध हैं, से पत्र मिले हैं, जिसमें उन्होंने इस्को / 'इस्को' आधुनिकीकरण परियोजना में भागीदारी की रुचि दिखाई है।

सेल ने एस बी आई--कैपिटल मार्किट लिमिटेड (एस०बी०आई०--सी०ए०पी०) को इस्को में निजी भागीदारी की संभावनाओं का पूरी तरह पता लगाने के लिये व्यवसायिक परामर्शदाता के रूप में रखा। अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्यवाही के एक भाग के रूप में, यह समझा जाता है कि एस०बी०आई०--सी०ए०पी० कापरो ग्रुप के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

"सेल" को एस बी आई --सी ए पी से रिपोर्ट मार्च, 1992 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है। तत्पश्चात् सरकार सुझावों पर विचार करेगी।

Light rail transport project for Hyderabad

*72. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of URB AN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have cleared a light rail transport project for Hyderabad;

(b) if so, the details of the proposal;

(c) the time frame for completion of the projects ; and

(d) whether Government are also considering a similar proposal for Visakhapatnam for providing urban transport facility?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRIMATI SHEILA KAUL) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

(d) No, Sir.

महाराष्ट्र में प्याज की कीमतों में गिरावट

*73. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में प्याज से अत्याधिक उत्पादन के कारण इसकी कीमत कम होकर 100 रुपये प्रति क्विंटल से भी नीचे तक पहुंच गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द प्याज-उत्पादकों से प्याज की खरीद करने के लिये राज्य-सरकार को सहायता देने पर विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के कब तक हटा लिये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (डा. बलराम जाखड़) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से एक मण्डी हस्तक्षेप योजना को पहले ही अन्तिम रूप दे दिया है, जिसमें 1-1-92 से 29-2-92 तक की अवधि में 30,000 मीटरी टन अच्छी औसत किस्म की प्याज की खरीद 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जायेगी। यह खरीद केन्द्रीय नोडल एजेंसी अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राज्य द्वारा मनोनीत एजेंसी द्वारा बराबरी के आधार पर की जायेगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत की गयी है कि राज्य सरकार पिछले वर्षों की हानियों सहित हानियों का वहन केन्द्र सरकार के साथ बराबरी के आधार पर करेगी और राज्य एजेंसी नियुक्त करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के मान-दण्डों के संबंध में अभी तक अपनी सहमति सूचित नहीं की है।

(घ) आयात-निर्यात नीति 1990-93 के अधीन, प्याज खुले सामान्य लाइसेंस (4) की श्रेणी में आता है और इसका निर्यात नेफेड के माध्यम से किया जाता है, जो सम्बद्ध जहाज व्यापारियों के साथ प्याज का निर्यात करते हैं। इस प्रकार, प्याज के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

74[Transforred to the 5th March,

Fool famine in Tripura

*75. DR. BAPU KALDATE :
SHRI M.S. GURUPADASWAMY :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government have made any on-the-spot assessment of the food famine in the inaccessible and remote villages in Tripura leading to starvation deaths;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what measures have been taken by Government to provide relief to the affected areas to prevent starvation deaths?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR) : (a) and (b) Senior Officials of Government of Tripura have visited inaccessible and remote villages. No case of starvation death has been reported from these villages.

(c) The State Government is implementing various schemes like Jawahar Rojgar Yojana and State Rural Employment Programme in all parts of Tripura particularly covering the hilly and interior areas to generate employment to the rural poor. Adequate availability of foodgrains is also ensured in critical areas by the State Government.

उत्तर प्रदेश में यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्त-पोषित कृषि परियोजनाएं

*76. श्री ईश दत्त यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में ऐसी कृषि परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं ; जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) इस प्रकार की सहायता के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जिला-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और उन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफलता मिली है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित दो चल रही कृषि परियोजनाओं के लिए यूरोपीय